International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 5.414 Volume 8, Issue 06, June 2021
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com

भारत और कोविड–19 : भारत पर कोरोना का प्रभाव एवं केंद्र सरकार द्वारा उससे निपटने के लिए उठाये गए महत्वपूर्ण कदम

डॉ० गीता
अस्सिटेंट प्रोफेसर
सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज बागपत

प्रस्तावना

विश्व स्वास्थ्य संगठन ॅ;भ्व्द्ध ने कोरोना वायर को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लकिन कोरोना का संक्रमण दुनियाभर में तेजी से फैल रहा है। अब तक इस वायरस के कारण दुनियाभर में लगभग 1.47 करोड लोग जुलाई 2020 तक संक्रमित हो चुके हैं। 6.95 लाख लोगो की मृत्यु 20 जुलाई 2020 तक हो चुकी है। भारत में 20 जुलाई 2020 तक 1119412 व्यक्ति संक्रमित पाये गये हैं जिनमें से 27514 लोगो की मृत्यु हो चुकी है। इसका प्रभाव व्यस्कों की तुलना में बुजुर्गों एवं बच्चों पर अधिक हुआ हैं साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में कोरोना वायरस का प्रसार अधिक हुआ है।

दुनिया भर के बड़े–बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोने की वैक्सीन बनाने में लगे हैं और उसमें सफलता भी मिली है। कोरोना काल में दुनिया भर के सामने अनेकों सामाजिक–आर्थिक समस्याएं आ खडी हुई है जिनका सामना सारी दुनिया कर रही है।

कोरोना वायरस क्या है?

कोरोना वायरस ;ब्वतवदं अपतनेद्ध कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह आरएनए वायरस होते हैं। इनके कारण मानवों में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है जिसकी गहनता हल्की (जैसे–सर्दी, जुकाम) से लेकर अति गम्भीर (जैसे–मृत्यु) तक हो सकती है। चीन के वूहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदाहरण है, जिसका संक्रमण सन् 2019–20 काल में तेजी से उभरकर 2019–20 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैला।ॅभ्व् ने इसका नाम ब्व्टप्क.19 रखा।

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

नाम की उत्पत्ति

लैटिन भाषा में ''कोरोना'' का अर्थ ''मुकुट'' होता है और इस वायरस के करणों के ईर्द–गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे ढांचे से इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखता है, जिस पर इसका नाम रखा गया है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो चन्द्रमा के चारों ओर किरण निकलती प्रतीत होती है, उसको भी कोरोना कहते हैं।

सार्स–कोव 2 (नोवल कोरोना वायरस)

यह वायरस भी जनवरी में आया है। ज्यादातर लोग जो चीन शहर के केन्द्र में स्थित हुआनन सीफूड होलसेल मार्केट में खरीदारी के लिए आते हैं या फिर अक्सर काम करने वाले लोग जो जीवित या नव वध किये गये जानवरों को बेचते थे इस वायरस से संक्रमित थे। चूँकि यह वुहान, चीन से शुरू हुआ, इसलिये इसे वुहान कोरोनावायरस के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि ॅभ्व ने इसका नाम सार्स–कोव 2 ें;त्ै.ब्वट 2द्व रखा है। कोरोना वायरस (सीओवी) का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से हैं जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था ॅभ्व के अनुसार बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी रखनी होती है। यह वायरस दिसंबर में 2019 में सबसे पहले चीन में पाया गया था।

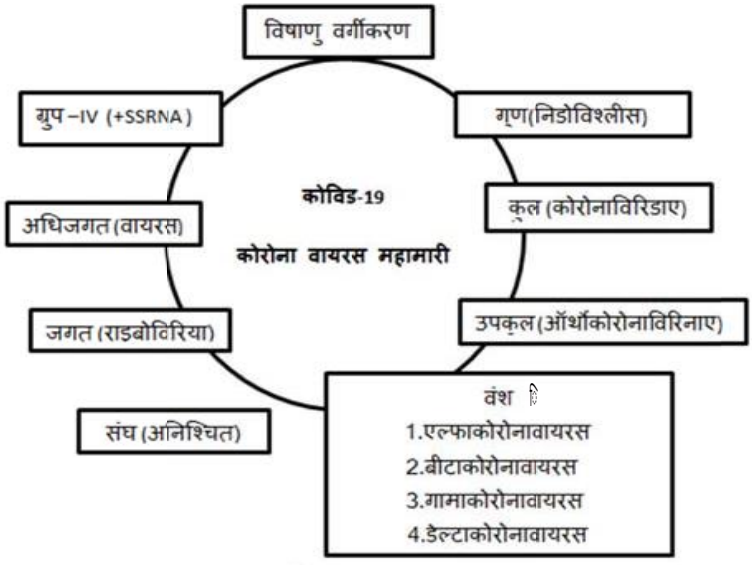

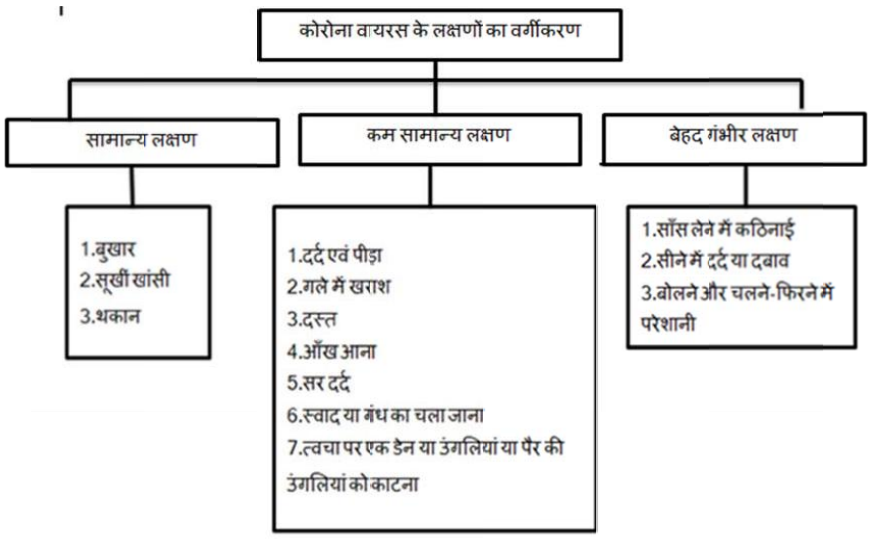

तालिका–1 : कोरोना संक्रमित मरीजों में लक्षणों का प्रतिशत

क्र0सं0	लक्षण	प्रतिशत
01	बुखार	88
02	खांसी और कफ	68
03	थकान	38
04	सांस लेने में तकलीफ	18
05	शरीर और सिर में दर्द	14
06	ठंड लगना	11
07	डायरिया के लक्षण	4

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अुनसार कोरोना वायरस से संक्रममित होने पर 88 प्रतिशत को बुखार, 68 प्रतिशत को खांसी और कफ, 38 प्रतिशत को थकान, 18 प्रतिशत को सांस लेने में तकलीफ, 14 प्रतिशत को शरीर और सिर में दर्द, 11 प्रतिशत को ठंड लगना और 4 प्रतिशत में डायरिया के लक्षण दिखते हैं। रंनिग नोज यानी नाक बहना कोरोना वायरस का लक्षण नहीं माना जा सकता है। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कई मामले ऐसे मिले हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आये हैं, इसलिए आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है–

➢ **कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाये तब**

- जब तक कोरोना वायरस के इलाज की सटीक दवा नहीं मिल पाती, तब तक बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाईया जा सकती है।
- जब तक रोगी ठीक न हो जाये, तब तक दूसरों से दूर रहे।
- वैक्सीन समय पर लें एवं किसी भी दशा में इसे अनदेखा न करे।

➢ **बचाव के उपाय**

- कोरोनो से मिलते-जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के माध्यम से फैलते हैं। इसलिए खांसते और छींकते समय मुंह को ढक कर रखें।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं, उनका पालन करना चाहिए।
- हाथों को बार-बार साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का प्रयोग भी किया जा सकता है।
- जिन व्यक्तियों में कोल्ड एवं फ्लू के लक्षण हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें।
- अंडे और मांस के सेवन से बचें।
- जंगली जानवरों के सम्पर्क में आने से बचे।
- हाथ साफ नहीं हो तो आंख, नाक और मुंह को छूने से बचे।
- सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा न करे।
- घर में मेहमान न बुलाये।
- घर का सामान किसी अन्य से न मंगाये।
- ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक स्थानों पर न जायें।
- अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज्यादा सर्तकता बरतें।

14 दिनों तक ऐसा करते रहे ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अग आप संक्रमित इलाके से आए है या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है। अतः घर पर रहें।

तालिका–2 : कोरोना वायरस से आयु अनुसार मृत्युदर

क्र0सं0	आयु वर्ग	मृत्युदर (प्रतिशत में)
01	0–9	0
02	10–39	0.2
03	40–49	0.4
04	50–59	1.3
05	60–69	3.6
06	70–79	8
07	80 से अधिक आयु	14.8

भारत में कोरोना की शुरूआत

भारत में कोरोना की शुरूआत मार्च महीने में हुई थी। सर्वप्रथम भारत में कोरोना केस केरल राज्य में पाए गये थे। यहां पर 3 व्यक्तियों में कोरोना का संक्रमण पाया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 6 केस सामने आये थे। इसके बाद यह वायरस पूरे देश में फैलता गया और 20 जुलाई 2020 तक कुल केस 11.6 लाख हो गए। इसमें से 7 लाख लोग वायरस से स्वस्थ हो चुके थे और 28 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक 3.15 लाख तमिलनाडू, 1.76 लाख दिल्ली, 1.23 लाख उत्तर प्रदेश 49247 थे जबकि लक्षद्वीप में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं था।

तालिका–3 : देश में सर्वाधिक कोरोना संक्रमण वाले राज्य

क्र0सं0	राज्य	कुल मरीज	स्वस्थ हुए	मृत्यु
01	महाराष्ट्र	3.15 लाख	1.70 लाख	11854
02	तमिलनाडू	1.76 लाख	1.22 लाख	2551
03	दिल्ली	1.23 लाख	1.03 लाख	3628
04	कर्नाटक	63772	23065	1331
05	आध्र प्रदेश	49650	22890	642
06	उत्तर प्रदेश	49247	29845	1146
07	गुजरात	48355	34901	2142
08	तेलगांना	45076	32438	415
09	पश्चिम बंगाल	4248	24883	1112
10	राजस्थान	29434	21730	559

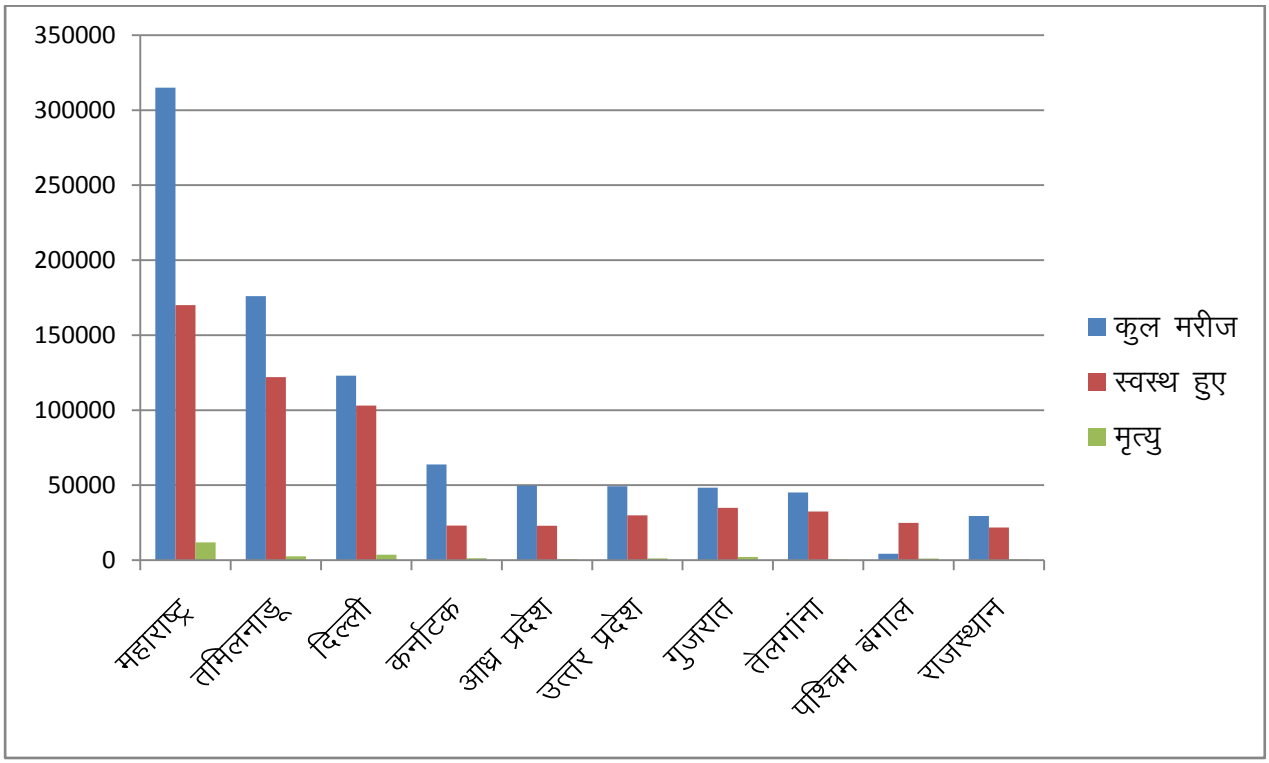

भारत में कोरोना वायरस के प्रभाव

देश में कोरोना वायरस की वजह देशी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गयी थी क्योंकि चार महीनों से देश की सभी आर्थिक गतिविधियां बंद थी, इसका असर देश के सभी वर्ग पर हुआ है। कोविड–19 महामारी ने देश के सामने अनेकों संकट खडे कर दिए हैं। देश में कोविड–19 के प्रभाव को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

नकारात्मक प्रभाव : कोविड–19 के कारण उत्पन्न दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं–

1. **आर्थिक संकट :** विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण भारत की इकोनोमी पर बडा असर पडने वाला है। कोरोना से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आयी। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर मात्र 5 प्रतिशत रह जाएगी तो वहीं 2020–21 में तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की दर में गिरावट आयेगी जो घटकर मात्र 2.8 प्रतिशत रह जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महामारी ऐसे समय में आयी है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय इकोनॉमी सुस्ती की मार झेल रही है, कोरोना वायरस के कारण इसपर और दबाव बढा है।
2. **सरकारी बचत और राजस्व में कमी :** देश में कोरोना की वजह से सरकार को लॉकडाअन लगाना पडा जिसके परिणामस्वरूप देश की सभी निजी एवं सरकारी आर्थिक गतिविधियां रूक गयी। इस

वजह से सरकार की आय बंद हो गयी। स्थिति यह हो गयी कि सरकार को देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकारी जमा पूंजी को खर्च करना पडा। इससे राजस्व कमी दर्ज की गयी।

3. **बेराजगारी में वृद्धि :** गौरतलब है कि 25 मार्च को देशभर में लॉकडाउन लगने के बाद देश में अप्रैल महीने में 23.52 प्रतिशत की रिकॉर्ड बेरोजगारी देखी गयी। इसके बाद मई महीने में भी 23.48 प्रतिशत की बेरोजगारी देखी गई क्योंकि ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां बंद थी, मई के पहले सप्ताह तो बेरोजगारी दर 27.1 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई थी। ब्डप्म् के आंकडों के अनुसार अप्रैल महीने में लगभग 12.2 करोड नौकरियां चली गई थी।

   सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा राज्य में फैली। आंकडों के अनुसार जून महीने में 33.6 प्रतिशत बेरोजगारी हरियाणा में रही। इसके बाद त्रिपुरा में 21.3 प्रतिशत और झारखण्ड में 21 प्रतिशत बेरोजगारी रही। ब्डप्म् के अनुसार जून में देश में कुल 37.3 करोड लोग रोजगार में थे। इस तरह जून में रोजगार की दर 35.9 प्रतिशत थी।

4. भूखमरी दर में वृद्धि : ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की एक रिपोर्अ के अनुसार भारत 30.3 स्कोर के साथ 117 देशों की सूची में भारत 102 वें स्थान पर था। इस महामारी के कारण देश में भूखमरी का स्तर और भी भयावह हो गया। ग्लोबल हंकर इंडेक्स के आंकडों के अनुसार भारत में 14.5 प्रतिशत लोग कुपोषित है।

5. जन-धन की हानि : देश में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण हजारों लोगों की जान गयी। सैंकडों महिलायें विधवा हो गयी, सैंकडों परिवार उजड गये। कितने ही बच्चे अनाथ हो गए। काम-धंधे बंद हो जाने के कारण लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गयी।

6. शिक्षण गतिविधियों पर रोक : लॉकडाउन के चलते देश के सभी छोटे बडे शिक्षण संस्थान बंद है जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों पढ़ाई बंद है। इस वर्ष बच्चों की अंतिम समय की परीक्षायें नहीं हो पायी है। सरकार के नियमानुसार बच्चों की आंतरिक आंकलन के द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश दिया गया है। सरकार ने बच्चों की पढाई के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफार्म एवं टीवी चैनल चला रखें हैं लेकिन बच्चों के जरूरी साधन नहीं होने के कारण वह अपनी पढाई नहीं कर पा रहे हैं।

7. रिवर्स माइग्रेशनः वैश्विक महामारी ब्व्टप्क्.19 के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों का पलायन भारी मात्रा में हुआ। लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से एकदम उलट है। सामान्य दिनों में हम देखते हैं कि रोजगार पाने व बेहतर जीवन जीने की आशा में गाँवों और कस्बों से महानगरों की ओर पलायन होता है, परंतु इस समय महानगरों से गाँवों की ओर हो रहा पलायन चिंताजनक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। सामान्य शब्दों में कहा जाये तो ''रिवर्स माइग्रेशन'' से आशय 'महानगरों और शहरों से गाँव एवं कस्बों को

ओर होने वाले पलायन से है'। बडी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गाँव की ओर प्रवासन हो रहा है जिसका कारण लॉकडाउन के बाद ही काम-धंधा बंद होना है।

8. कृषि पर प्रभाव : भारत, जोकि एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, वो भी इससे अछूता नही रहा है और 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर सिर्फ 119 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कोरोना वायरस के बढते प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने मार्च में प्रथम चरण के लॉकडाउन का ऐलान किया जब अधिकतर फसलों की कटाई का समय होता है। वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से मनाही होने के कारण, कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर, कंबाइड हार्वेस्टर तथा कुशल श्रमिकों के अनुपलब्धता ने मार्च महीने में कृषि में एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी। खरीफ फसलों की बुवाई तथा जरूरत के संसाधनों जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक की उपलब्धता भी एक प्रश्न खडा करती है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में कृषि कार्य में छूट देने का ऐलान किया और जरूरत की सभी सामग्रियों के खरीदी के लिए दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया और देश भर के किसानो ने सरकार के इस फैंसले का स्वागत किया।
9. भारत के व्यापार पर कोरोना का प्रभावः संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवेलपमेंट ने खबर दी कि कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया की 15 सबसे बडी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत भी है। चीन में उत्पादन में आई कमी का असर भारत से व्यापार पर भी पडा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को करीब 3418 करोड डॉलर तक का नुकसान उठाना पड सकता है। यूरोप के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी ने भी 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की गति का पूर्वानुमान 1.1 प्रतिशत घटा दिया है। ओईसीडी ने पहले अनुमान लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.2 प्रतिशत रहेगी लेकिन अब उसने इसे कम करके 5.1 प्रशित कर दिया।

सकारात्मक प्रभाव : कोरोना वायरस महामारी ;ब्व्टप्क.19द्ध से पर्यावरण पर कैसे सकारात्मक प्रभाव पडा है-

- **प्रदूषण स्तर कम हो गया हैः** कोरोना वायरस महामारी के चलते एक साथ देश और दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया। इससे न केवल उद्योग-धन्धे, कल-कारखाने बंद हो गये बल्कि लोगों की गाडियां चलाने पर रोक भी लग गई। इससे प्रदूषण स्तर बहुत कम हो गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे विडियो और तस्वीरों शेयर की गई हैं, जिनमें हिमालय को उत्तर भारत के राज्यों से देखा गया है।
- **हवा की गुणवत्ताः** लॉकडाउन के चलते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम हुआ है जबकि प्रदूषण स्तर भी कम हुआ है। इससे हवा साफ हो गई और पर्यावरण में हरियाली छा गयी।

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

- **नदियों का पानी स्वच्छ हो गयाः** लॉकडाउन से गंगा और यमुना का पानी स्वच्छ और कंचन हो गया। इससे पहले लोग नदियों में कचना फेंक देते थे, लेकिन कोरोना महामारी में लोगों के घरों से निकलने पर मनाही थी। साथ ही कारखानों से निकलने वाले खराब अवशेष भी नदियों में नहीं फेंका जा रहा था जिससे नदियों का पानी साफ हो गया।
- **वन्य जीवों को नया जीवन मिलाः** कोरोना वायरस महामारी से पहले वन्य जीव आजाद जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से वन्य जीव उन्मुक्त होकर जंगल में पहले की भांति विचरण कर रहे थे, विशेषतया पशु तस्करी का खतरा भी कम हो गया।
- **ओजोन परत में हुआ छेद भराः** कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में एक और बडी कामयाबी प्रकृति को मिली है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ओजोन परत पर हुआ इतिहा का सबसे बडा छेद भर गया है। वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव यानी नार्थ पोल के ऊपर ओजोन लेयर में एक 10 लाख वर्ग किमी0 का छेद होने की पुष्टि की थी। वैज्ञानिकों के अनुसार लॉकडाउन के चलते प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। इसका फायदा ये हुआ कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का छेद अपने आप ठीक हो गया। नासा के अनुसार नार्थ पोल यानी धरती का आर्कटिक वाले क्षेत्र के ऊपर एक ताकतवर पोलर वर्टेक्स बना हुआ था, जो अब खत्म हो गया हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओजोन परत के छेद का मुख्य कारण बादल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। इन तीनों की मात्रा स्ट्रेटोस्फेयर में बढ गई थी जो ओजोन परत को पतला कर रहे थे जिससे छेद बडा होता जा रहा था। इसमें प्रदूषण का भी प्रभाव रहता है लेकिन लॉकडाउन के चलते प्रदूषण कम होने के कारण इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले।

कोरोना संकट (कोविड–19) से प्रभावित जनता को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किये गये उपाय

1. **प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति**
    - प्रवासी कामगारों के लिये सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रति कामगार दो महीनों अर्थात मई और जून 2020 के लिये प्रति महीने प्रति कामगार 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न और प्रति परवार 1 किलोग्राम चना का मुफ्त आंवटन किया गया।
    - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले अथवा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में बिना राशन कार्ड वाले ऐसे प्रवासी कामगार भी इस योजना के पात्र होंगे, जो वर्तमान में किसी क्षेत्र में फंसे हुए हैं।
    - राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इस योजना के अन्तर्गत लक्षित वितरण के लिये एक तंत्र विकसित करने का परामर्श दिया गया।

- इसके लिए 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 50,000 मीट्रिक टन चने का आवंटन किया गया। इस योजना पर होने वाला कुल 3,500 करोड रूपये के व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया गया।

2. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना का विस्तार

- राशन कार्डो की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना (एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना) का 23 राज्यों तक विस्तार किया गया।
- इसके माध्यम से अगस्त 2020 तक राशन कार्डो की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के द्वारा लगभग 67 करोउ लाभार्थियों यानी च्कै के अन्तर्गत आने वाली 83 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लाया गया।
- 100 प्रतिशत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लक्ष्य का मार्च 2021 तक प्राप्त कर लेने का निश्चय किया गया।
- इस योजना से एक प्रवासी कामगार और उनके परिवार के सदस्य देश की किसी भी ''फेयर प्राइस शॉप'' से च्कै का लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। इससे स्थान परिवर्तन करने वाले प्रवासी कामगार देश के किसी भी हिस्से में च्कै लाभ लेने में सक्षम हो जाएंगे।

3. सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना

- केन्द्र सरकार प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिये सस्ते किराये पर रहने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू करेगी। सस्ते किराए के ये आवासीय परिसर प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों और छात्रों आदि को सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करेंगे।
- वित्त मंत्री के अनुसार, यह कार्य शहरों से सरकारी वित्तपोषित मकानों को रियायती माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी ;च्च्द्ध मॉडल के तहत सस्ते किराये के आवासीय परिसरों के रूप में परिवर्तित करके किया गया।

4. शिशु मुद्रा ऋण के तहत ब्याज की छूट

- भारत सरकार 50,000 रूपये से कम शिशु मुद्रा ऋण लेने वाली में शीघ्र भुगतान करने वाले लोगों को 12 महीनों की अवधि के लिये 2 प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान की गयी।
- शिशु मुद्रा ऋण लेने वाले लोगों को इस शोषण के तहत लगभग 1500 करोड रूपये की राहत निर्धारित की गयी।

5. स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5000 करोड रूपये की ऋण सुविधा

- उल्लेखनीय है कि स्ट्रीट वेंडरों पर मौजूदा स्थिति का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पडा है, उनको ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिये एक महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की गयी ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके।
- इस योजना के तहत प्रत्येक उद्यम के लिये 10000 रूपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की बैंक ऋण सुविधा दी गयी। ज्ञात हो कि यह योजना शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी इलाकों में व्यवसाय करते हैं।
- अनुमान के अनुसार, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे और उन तक 5000 करोड रूपये का ऋण प्रवाहित होगा।

6. रोजगार सृजन के लिए कैम्पा फंड का उपयोग

- क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 6000 करोड रूपये की राशि का प्रयोग शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्यों, वन संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबन्धन आदि में किया गया।

7. किसानों के लिए 30000 करोड रूपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी

- ग्रामीण सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की फसल ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 30000 करोड रूपए की अतिरिक्त पुनर्वित्तीयन सहायता प्रदान करने की योजना बनायी गयी।
- देश भर में इससे लगभग 3 करोड किसानों को फायदा मिलने का अनुमान लगाया गया जिनमें अधिकांश छोटे और सीमांत किसान शामिल थे, इससे किसानों की रबी की फसल कटाई के बाद और खरीफ फसल की मौजूदा जरूरते पूरी होंगी।

8. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार

- ब्व्टप्क:19 और इसके नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन से औद्योगिक गतिविधियों के बंद होने के कारण पिछले कुछ दिनों में देश में शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बडी संख्या में मजदूरों का पलायन देखने को मिला।

- ऐसे में आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बढती मांग को पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत 40000 करोड रूपए की अतिरिक्त धनराशि जारी करने की घोषणा की।
- वर्ष 2006 में 200 जिलों से शुरू किये गए मनरेगा कार्यक्रम के तहत हाल के वर्ष 2010–11 (5.5 करोड परिवार) के बाद पुनः रोजगार की मांग में काफी वृद्धि देखने को मिली है। (2018–19 में 5.27 करोड और 2019–20 में 5.47 करोड)
- केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार मई 2020 में मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में 40–50 प्रतिशत वृद्धि देखी गयी।
- हाल ही में केन्द्र सरकार ने मनरेगा के तहत औसत दैनिक मजदूरी को 182 बढाकर 202 रूपए कर दिया था।

9. स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रस्तावित सुधार

- केन्द्रयी वित्तमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों हेतु स्वास्थ्य और देखभाल केन्द्रों के सरकारी खर्च में वृद्धि और हर जिले में संक्रामक रोगों के लिये विशेष अस्पताल तथा ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की बात कही।
- हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों के संदर्भ में किसी वित्तीय परिव्यय की जानकारी नहीं दी गयी।

10. शिक्षा क्षेत्र से जुडी योजनाएं

- ब्व्टप्क:19 और लॉकडाउन के कारण हो रहे अकादमिक नुकसान को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा ‘‘पीएम ई–विद्या’’ योजना की घोषणा की गई।
- इस योजना के तहत छात्रों को विभिन्न माध्यमों के जरिये शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी, साथी ही कक्षा 1 से 12 के लिये अलग–अलग टीवी चैनलों की शुरूआत भी की जायेगी।
- इससे पहले केन्द्र सरकार ने इस माह के अंत तक देश में शीर्ष के 100 विश्वविद्यालयों के द्वारा ऑनलाईन कक्षाओं को चालू किये जाने की योजना की घोषणा की थी।

लाभ

- केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा के लिये प्रस्तावित राशि में वृद्धि के निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की चुनौती को कम करने में सहायता प्राप्त हुई।

- ब्व्टप्क.19 के कारण अगले कुछ महीनों तक रोजगार के अवसरों में कमी बनी रह सकती है, ऐसे में मनरेगा के तहत श्रमिकों की दैनिक आय में वृद्धि से इस योजना से जुडे परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाई गयी।
- ब्व्टप्क.19 और लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारों की आय और जीडीपी में भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया, ऐसे में ऋण सीमा को 3 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत करने से राज्य सरकारों को वर्तमान आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद प्रदान की गयी।
- लॉकडाउन का प्रभाव अनय क्षेत्रों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिला है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों के छात्र इंटरनेट के माध्यम से कुछ सीमा तक अपनी शिक्षा जारी रखने में सफल रहे थे पंरतु ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों के लिय एक चुनौती थी, ऐसे में पीएम ई-विद्या योजना के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों में ऑनलाईन शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की सकी।

कोरोना महामारी में केन्द्र सरकार द्वारा उठाये कदम कितने सफल हुए

कोरोना संकट महामारी के निपटने के लिए देश भर में किए लॉकडाउन के चलते सारे कारोबार और उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हैं। दिहाडी मजदूरों के सामने आजीविका का संकट खडा था तो गरीबों के लिए अपना और अपने परिवार के लिए दो जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसी मुश्किल घडी में केन्द्र की पांच योजनाएं गरीबों की मददगार साबित हुई। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गो और किसानों को नकद भुगतान कर आर्थिक मदद पहुंचाई है।

(1) जनधन खाताः 3 महीने 500-500 रूपये की मदद

- कोरोना संक्रमण के संकट में गरीबों के लिए जनधन बैंक खाता मददगार बना। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को अपना घर चलाने में आर्थिक परेशानी नहीं हो, इसके लिए केन्द्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिलाओं के जनधन खातों में 500-500 रूपए की किश्त दी। सरकार ने तीन महीने अप्रैल, मई और जून तक 20 करोड महिलाओं को यह सहायता देने का फैंसला किया। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 2.82 करोड वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को 1405 करोड रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।
- देश की 20.05 करोड महिला जनधन खाताधारकोकं के खाते में 500 रूपए की पहली किश्त के तौर पर 10025 करोड रूपए भेजे गए। इसमें से करीब 8.72 करोड महिला जनधन खाताधारकोकं ने

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

खातों से निकासी भी की। वहीं 5.57 करोड महिला जनधन खाताधारकों के खाते में दूसरी किश्त के तौर पर 2785 करोड रूपए भेजे गए।

(2) खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज

- लॉकडाउन में खाद्य सुरक्षा योजना गरीबों के लिए काफी बडा सहारा बनी है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन देने का ऐलान किया। केन्द्र सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दो रूपए किलो गेहूं और तीन रूपए किलो चावल प्रति व्यक्ति पांच किलो दे रही थी। कोरोना काल में जो अतिरिक्त अनाज दिया गया, मोदी सरकार ने उसे तीन महीने के लिए फ्री कर दिया।
- देश में 81 करोड लाभार्थी थे इसके ऊपर कुल मिलकार 46 हजार करोड रूपया खर्च किया गया। गेहूं-चावल के अलावा दाल दी गई। 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने 67.65 लाख टन खाद्यान्न उठाया।
- इस योजना का विस्तार नवम्बर 2020 तक किया गया और नवम्बर 2020 तक लोगों को अतिरिक्त मुफ्त राशन वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(3) पीएम किसान सम्मान निधि योजना

- कोरोना संकट में किसानों के खाते में सरकार ने पैसे भेजने का काम किया जो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी गई। पीएम किसान योजना के तहत 71 हजार करोड रूपया 9 करोड 34 लाख किसानों को दिया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में सीधे 2000 रूपए की आर्थिक मदद पहुंचायी गई। इस योजना में छोटे किसानों के खाते में हर साल 3 किश्तों में 6000 रूपए की राशि जमा की जाती है। इसके अलावा करीब 3 करोड किसानों ने अपने कर्ज पर 3 महीने के मोरेटोरियम का फायदा भी दिया।

(4) मनरेगा रोजगार सृजन में मददगार

लॉकडाउन के दौरान मरनेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए रोजी रोटी का सहारा बनी है। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते घर वापसी करने वाले मजदूरों के लिए भी लाइफलाइन बन रही है। कोरोना संकट के चलते केन्द्र सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रूपए से बढाकर 202 रूपए कर दिया है, जिसे एक अप्रैल से लागू भी कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 33300 करोड रूपए की राशि मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत की है। इसमें से 20225 करोड रूपये की राशि पूर्व वर्षो की मजदूरी का बकाया देने के लिए जारी की है।

(5) उज्जवला योजना के जरिए फ्री गैस

लॉकडाउन में केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत उज्जवला योजना के लाभार्थियों को भी शामिल किया है। मोदी सरकार ने उज्जवला योजना के तहत आने वाले लोगों को तीन

महीने तक मुफ्त रसोई गैस देनी शुरू की। सरकार ने प्रति लाभार्थियों के खाते में घरेलू गैस सिलेण्डर के लिए 753 रूपए भेजे। उज्जवला स्कीम के तहत 14.2 किलोग्राम वाले 3 सिलेंडर ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दिए गये। केन्द्र सरकार ने मुफ्त गैस के लिए गरीबों के लिए 4.82 करोड रूपए वितरित किये।

निष्कर्ष

भारत में कोरोना का संकट प्रभाव व्यापक रूप से देश के गरीब और पिछडे वर्ग पर सर्वाधिक हुआ। इसके अंतर्गत देश का दिहाडी मजदूर आता है जो अपने परिवारों का जीवनयापन रोजमर्रा की आय के द्वारा करते थे। परन्तु कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पडा जिसके परिणामस्वरूप देश की समस्त आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां बंद हो गयी। इस स्थिति में लोगों की आय बंद हो गयी और उन्हें मजबूरन अपने घरों को पलायन करना पडा। लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने एक वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये जिनके तहत लोगों को मुफ्त राशन, बैंक खातों में डायरेक्ट नकद भुगतान किया गया, उज्जवला योजना के तहत तीन महीनों तक मुफ्त गैस दिया गया। दिव्यांगों, विधवाओं एवं बुजुर्गों को अतिरिक्त पेंशन दी गयी, अपने गृह राज्य लौटे मजदूरों को मनरेगा और जल मिशन के तहत रोजगार देने का प्रबंध किया गया। परन्तु इन सब उपायों के बावजूद ऐसे करोडों लोग ऐसे थे जिनके पास न तो राशन कार्ड था न ही बैंक खाता न रहने के लिए घर। ऐसे लोगों की मदद करने में केन्द्र सरकार की ये सब योजनाएं भी असफल साबित हुई। न सिर्फ कोरोना संकट में बल्कि सामान्य दिनों में भी ये वर्ग तमाम सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में सरकार को एक ऐसी प्रणाली तैयार करनी चाहिए जोकि लोगों के कल्याण के लिए भी योजना बनाये। उसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिले ताकि देश का हर वर्ग विकास कर सके और साथ ही हमारा देश भी विकास कर सके।